बड़े शहरों में मल-जल व्ययन की योजनाएं

3906. **श्री अजीत जोगी:**
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े शहरों में मल-जल व्ययन की कोई योजनायें तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई राशि कितनी-कितनी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) से (ग) जी, नहीं। जल निकासी और मलजल व्ययन राज्य का विषय होने के नाते, मलजल स्कीमों की योजना बनाना और उनका निष्पादन करना राज्य सरकारों का दायित्व है। जल और मलजल व्ययन के क्षेत्र में केन्द्र प्रवर्तित कोई स्कीम नहीं है तथा केन्द्र प्रवर्तित मेगासिटी स्कीम, जो पांच मेगा शहरों नामतः बम्बई, बंगलौर, मद्रास, हैदराबाद और कलकत्ता में चलाई जा रही है, के तहत निकासी और मलजल प्रबन्ध/व्ययन से सम्बन्धित कुछ परियोजनाएं हैं। मेगा शहरों में स्वीकृत मलजल एवं निकासी स्कीमों बाबत सूचना इस प्रकार है:—

क्र०सं०	शहर का नाम	मलजल/निकासी की स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1.	कलकत्ता	14	23.78
2.	हैदराबाद	—	10.00
3.	मद्रास	2	11.94
4.	बम्बई	1	2.07
5.	बंगलौर	—	—
	योग	17	47.29

जम्मू और कश्मीर द्वारा विकास-निधियों का उपयोग

3907. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि तथा खर्च न की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासुब्रह्मण्यन): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 1053.25 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में से राज्य सरकार द्वारा 1023.71 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी और शेष 29.54 करोड़ रुपये की राशि बिना खर्च किए रह गई।

Power Requirement of Madhya Pradesh

3908. SHRI RAGHAVJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the over all requirement of power for Madhya Pradesh by 2000 AD;

(b) whether Government propose to formulate any new plans in order to meet that requirement;

(c) if so, the features thereof;

(d) the total expenditure likely to be incurred thereon; and

(e) by when it is likely to become operative?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENU-GOPALACHARI): (a) As per the forecast made in the fourteenth Electric Power Survey Report, the requirement of power for Madhya Pradesh for the year 2000 AD will be 34.757 Billion Units.

(b) to (e) The capacity addition programme for the Ninth Five Year Plan (1997-2002) for the entire country would